'अप्प दीपो भव'

वॉयस ऑफ बुद्धा

Postal Reg. No.-DL(ND)-11/6144/2013-15
WPP Licence No.- U(C)-101/2013-15
R.N.I. No. 68180/98

प्रकाशन तिथि– 15 जुलाई, 2013

मूल्य : पाँच रूपये

प्रेषक : डॉ0 उदित राज (राम राज) चेयरमैन - जस्टिस पब्लिकेशंस, टी-22, अतुल ग्रोव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001, फोन : 23354841-42

Website : www.uditraj.com E-mail: dr.uditraj@gmail.com

● वर्ष : 16 ● अंक 16 ● पाक्षिक ● द्विभाषी ● 1 से 15 जुलाई, 2013

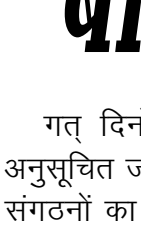

असत्य बोलने से दूर रहे।

-गौतम बुद्ध

शिक्षा के व्यवसायीकरण के विरोध में 8 सितंबर को राष्ट्रीय सम्मेलन

स्थान : कांस्टीट्यूशन क्लब, दिल्ली।

गत् एक दशक से शिक्षा सबसे ज्यादा सुरक्षित एवं कमाने वाला व्यापार हो गया है। शिक्षा से ही कोई देश आगे जाता है और इसके अभाव में पतन भी होता है। भले ही भारत आर्थिक तरक्की कर रहा हो लेकिन इसका फल सबको मिले और वृद्धि लगातार बनी रहे, उसके लिए शिक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। गरीबी हटाने के तमाम उपाय सरकार करती रहती है लेकिन यह मिटने वाली दिखती नहीं, जब तक कि देश शिक्षित नहीं हो जाता। जिस दिन इस देश में समान शिक्षा हो जाएगी, उसी दिन भारत दुनिया का नेता बन जाएगा। वर्तमान शिक्षा का जोर नौकरी लेने के लिए है न कि सही ज्ञान के फैलाव के लिए। जो भी शिक्षा सरकार के द्वारा उपलब्ध है, उसका व्यवसायीकरण तेजी से होता जा रहा है। गुणवत्ता वाली शिक्षा अमीरों तक सीमित होती जा रही है।

दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा चार वर्ष का स्नातक कार्यक्रम लागू कर दिया गया है, यह कहते हुए कि यह रोजगार परक है, क्योंकि ऐसा अमेरिका में भी है। जो कुछ अमेरिका में हो रहा है, क्या हमारे यहां भी हो?जब भी सवाल खड़े किए जाते हैं तो जवाब यही रहता है कि ऐसा अमेरिका में हो रहा है। अमेरिका एवं यूरोप में उच्च शिक्षा प्राप्त करने में रूचि बहुत कम लोगों की होती है, लेकिन हमारे समाज की सच्चाई कुछ और है। वहां पर चाहे उच्च शिक्षित व्यक्ति की आय हो, सामाजिक प्रतिष्ठा या हैसियत, कम शिक्षित व्यक्ति को खास प्रभावित नहीं करती । हमारे यहां उच्च शिक्षा का संबंध उच्च आय, प्रतिष्ठा, ज्ञान, अवसर आदि बहुत सारी बातों से जुड़ा हुआ है। दिल्ली विश्वविद्यालय की शिक्षा नीति 10+2+4 की है और इसका छुपा हुआ एजेंडा है कि पीछे के दरवाजे से निजीकरण की प्रक्रिया को तेज करना और उच्च शिक्षा को इतना महंगा बना देना कि अनुसूचित जाति, जन जाति, पिछड़े, ग्रामीण एवं गरीब वहां तक पहुंचने की हिम्मत ही न कर सकें। प्रथम वर्ष में अंग्रेजी, गणित एवं विज्ञान पढ़ना अनिवार्य कर दिया

शेष पेज 3 पर...

बोधगया पर आतंकी हमले की निंदा-उदित राज

गत् दिनों 8 जुलाई को अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, डॉ0 उदित राज ने कहा कि 7 जुलाई की प्रातःकाल में बोधगया बुद्धविहार एवं आसपास के विदेशी मिशन पर कई बम फूटे जिसकी वजह से काफी क्षति पहुंची। उसके बाद से न केवल देशी पर्यटक और यहां के बौद्ध भिक्षु भयभीत हैं बल्कि जितने विदेशी मिशन हैं, उन पर भी भारी आतंक का साया मंडरा रहा है। नवंबर, 2012, 21 जून, 2013 एवं 3 जुलाई 2013 को जब इंटलीजेंस ब्यूरो, दिल्ली पुलिस आदि एजेंसियों ने बिहार सरकार को आगाह कर दिया था कि बोधगया पर आतंकी हमले कभी भी हो सकते हैं, तो फिर भी बिहार की सरकार ने समय रहते उचित कदम नहीं उठाए और परिणाम सामने हैं। इसके लिए बिहार सरकार, जो सुशासन के लिए

शेष पेज 3 पर...

पार्वती योनि

नेहा नरूका

ऐसा क्या किया था शिव तुमने?
रची थी कौन–सी लीला?
जो इतना विख्यात हो गया तुम्हारा लिंग
माताएं बेटों के यश, धन व पुत्रादि के लिए
पतिव्रताएं पति की लंबी उम्र के लिए
अच्छे घर–वर के लिए कुंवारियां
पूजती है तुम्हारे लिंग को,
दूध–दही–गुड़–फल–मेवा वगैरह
अर्पित होता है तुम्हारे लिंग पर
रोली, चंदन, महावर से
आड़ी–तिरछी लकीरें काढ़कर,
सजाया जाता है उसे
फिर ढ़ोक देकर बारंबार
गाती हैं आरती
उच्चारती हैं एक सौ आठ नाम
तुम्हारे लिंग को दूध से धोकर
माथे पर लगाती है टीका
जीभ पर रखकर
बड़े स्वाद से स्वीकार करती हैं
लिंग पर चढ़े हुए प्रसाद को
वे नहीं जानती कि यह
पार्वती की योनि में स्थित
तुम्हारा लिंग है,
वे इसे भगवान समझती हैं,
अवतारी मानती हैं,
तुम्हारा लिंग गर्व से इठलाता,
समाया रहता है पार्वती योनि में,
और उससे बहता रहा है
दूध, दही और नैवद्य...
जिसे लांघना निषेध है
इसलिए वे औरतें
करती हैं आधी परिक्रमा
वे नहीं सोच पातीं
कि यदि लिंग का अर्थ
स्त्रीलिंग या पुल्लिंग दोनों है
तो इसका नाम पार्वती लिंग क्यों नहीं?
और यदि लिंग केवल पुरुषांग है
तो फिर इसे पार्वती योनि भी
क्यों न कहा जाए?
लिंग पूजकों ने
चूंकि नहीं पढ़ा 'कुमारसंभव'
और पढ़ा तो 'कामसूत्र' भी नहीं होगा,
सच जानते ही कितना हैं?
हालांकि पढ़े–लिखे हैं,
कुछ ने पढ़ी है केवल स्त्री–सुबोधिनी
वे अगर पढ़ते और जान पाते
कि कैसे धर्म, समाज और सत्ता
मिलकर दमन करते हैं योनि का,
अगर कहीं वेद–पुराण और इतिहास के
महान मोटे ग्रंथों की सच्चाई!
औरत समझ जाए
तो फिर से पूछ सकती हैं
संभोग के इस शास्त्रीय प्रतीक के–
दो नाम नहीं हो सकते थे क्या?
वे पढ़ लेंगी
तो निश्चित ही पूछेंगी,
कि इस दृश्य को गढ़ने वाले
कलाकारों की जीभ
क्या पितृसमर्पित सम्राटों ने कटवा दी थी
क्या बदले में भेंट कर दी गई थी
लाखों अशर्फियां,
कि गूंगे हो गए शिल्पकार
और बता नहीं पाए
कि संभोग के इस प्रतीक में
एक और सहयोगी है
जिसे पार्वती योनि कहते हैं।

(साभार–बैकवर्ड)

कहानी

शिवलिंग

बुद्धशरण हंस

महेर की पहाड़ी पर पत्थरों को छीलते तराशते चीतू के बीस साल गुजरे हैं। उसके बाप–दादों ने भी वही काम करके अपनी जिंदगी गुजारी है। बाप–दादों से यही कला चीतू को विरासत में मिली है। वह रोज पत्थरों को काटता, तराशता, अत्यंत बारीकी से मूर्तियों का निर्माण करता। यही उसकी खेती है। पत्थरों के खेत, छेनी, हथौड़ियों के बीच तथा अपनी कला को खाद–पानी दे चीतू मूर्तियों की फसल उपजाता। गया जैसी धार्मिक जगहों में उसकी मूर्तियां खूब बिकती। पत्थर काटते–काटते उसकी जाति बदल गई। वह ''पत्थर कट्टा'' हो गया।

दो सप्ताह से चीतू मलेरिया से परेशान है। सावन का महीना आ रहा है। मूर्तियों की मांग बढ़ गई है। कई ग्राहक शिवलिंग की मांग कर गए हैं। मगर चीतू बीमार है। वह चादर ओढ़े अपनी झोपड़ी में पड़ा है। पत्थरों को देखकर तरसता है सोचता है– ''बोखार भी साला क्या आफत है, जब तब टपक जाता है। साला सैकड़ों काम नाश हो जाता है। अच्छा होता तो अब तक कितना शिवलिंग बनाकर पैसा पीट लेता। सबसे आसान है लिंग बनाना। न आंख बनाना पड़ता है, न कान, न मुंह, न दांत। बस लोढी को चिकना दो लिंग तैयार। इ भी कोई मूर्ति हुई। मगर जिसे देखो लिंग के लिए दौड़ा चला आ रहा है। लोग भी कैसे हैं।'' चीतू हंसा। उस तप्त ज्वर में वह खिलखिला उठा।

वह और सोचता, लेकिन झोपड़ी के बाहर किसी की आवाज के विचार से उसके विचार तन्तु टूट गए।

''अरे है कोई ?'' ... किसी ने पुकारा।

''हां, हां मालिक! हैं'' ... चादर फेंककर चीतू झोपड़ी से आहर आया। देखा एक सेठ जी पुकार रहे हैं।

''कहिए मालिक, क्या चाहिए ?'' ... चीतू ने पूछा।

''अरे भाई, मुझे शिवलिंग चाहिए और अभी चाहिए। बना हुआ हो तो दे दो।'' सेठ ने अपनी तोंद पर हाथ फेरकर कहा।

''मालिक दो सप्ताह से काम बंद है। मलेरिया से परेशान हूं। बना हुआ तो नहीं है, कहिए तो बना दूं।'' चीतू ने कहा।

''कब तक बन जाएगा ?''–सेठ कुछ जोड़कर बोला।

''किसी दिन भी आ जाइए।'' –चीतू ने कहा। उसे भी मजदूरी की सख्त जरूरत थी।

''कल आऊं बन जाएगा ?'' – सेठ ने पूछा।

''मालिक कल तो नहीं परसों आप ले लीजिए।'' चीतू बोला।

''ठीक है। परसों ही सही। लेकिन धोखा न हो'' –सेठ ने अपने शब्दों को भारी बनाकर कहा।

''लिंग घर के लिए चाहिए या बाहर के लिए ?'' चीतू ने जानना चाहा।

''घर के लिए। जरा सुंदर बनाना'' – सेठ ने कहा।

''कितना बड़ा लिंग चाहिए ?''–चीतू ने पुनः पूछा।

''यही करीब एक फुट का'' –सेठ ने कहा।

चीतू फूट–फाट जानता न था। उसने अपने बांये हाथ से दाहिने हाथ की केहुनी पकड़ कर कहा– ''इतना बड़ा ?''

''अरे! यह तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक इसका आधा चाहिए।'' सेठ ने चीतू को समझा कर कहा।

''लिंग मोटा रहेगा या पतला ?'' –चीतू ने आगे जिज्ञासा की।

''न ज्यादा मोटा न ज्यादा पतला। ऐसा हिसाब से बना दो जो देखने में अच्छा लगे।''

''लिंग नुकीला कर दूंगा या चौरस ?'' –चीतू ने अंतिम जिज्ञासा की।

चीतू के इस तरह के तार्किक प्रश्नों से सेठ चिढ़ गया। लिंग के संबंध में ज्यादा छीछालेदार उसे अच्छा नहीं लगा। उसने उकता कर कहा– ''क्या उलूल–जलूल बातें पूछ रहे हो ? तुम कलाकार हो, तुम समझते नहीं कि लिंग कैसा होना चाहिए ?''

सेठ का झल्लाना चीतू को अच्छा नहीं लगा। फिर भी उसने संयत स्वर में कहा– ''मालिक कलाकार तो हूं, लेकिन ग्राहक की इच्छा–अनिच्छा तो जाननी ही पड़ती है। पीछे पसंद–नापसंद पर कीच–कीच करने से क्या फायदा।''

सेठ आदेश देकर चलता बना। चीतू अपनी छेनी और हथौड़ी लेकर एक काले पत्थर से खेलने लगा–ठक्–ठक्, ठुकुर–ठुकुर।

ठीक तीसरे दिन सेठ आ धमका।

''क्या भाई! माल तैयार है?'' सेठ ने आते ही पूछा। मलेरिया से पीड़ित रहकर भी चीतू शिवलिंग तैयार कर चुका था। दूसरी कोई मूर्ति बनाना होता, चीतू कभी न बनाता। लेकिन शिवलिंग बनाने में भला क्या मेहनत। चीतू ने लिंग निकाल कर सेठ को पकड़ा दिया। सेठ ने लिंग को उलट–पुलट कर देखा। लिंग बिल्कुल उसके मन के विपरीत था।

''यह शिवलिंग है या बच्चियों की चक्की का खिलौना'' –सेठ ने भिन्नाकर कहा।

''क्या हुआ मालिक ?'' चीतू घबड़ाया।

''खाक हुआ। तुमने लिंग इतना पतला बना दिया है और यह ... डबरा जैसा चौड़ा, लगता है जैसे बड़ा ढक्कन हो।'' सेठ को बीच में बात को स्पष्ट करने में कुछ दिक्कत हुई।

''ठीक ही तो है मालिक। आपने जैसा कहा था वैसा ही तो बनाया हूं। लिंग देखिए कितना अच्छा है। घेरे से क्या लेना–देना, पानी ही बहेगा इसमें।'' चीतू ने सेठ को समझाया।

चीतू की बात से सेठ को बहुत गुस्सा चढ गया। उसे बिगड़ कर कहा – ''अरे मूर्ख कुछ जानता भी है या ऐसे ही शिवलिंग बनाता है ?''

''यही बनाते, समझते तो जिंदगी की बीस वर्षात काट ली है मालिक।'' चीतू ठीसुआ गया। उसकी समझ में नहीं आया कि लिंग में क्या गड़बड़ी रह गई है।

''खाक समझते हो। इतनी भी समझ तुम्हें नहीं कि जितना बड़ा लिंग रहेगा उसी के अनुपात में भग।'' लिंग के चारों ओर अत्यधिक चौड़े गढे में उंगली घूमाकर सेठ ने चीतू को समझाना चाहा।

''मालिक ज्यादा पानी बहने के ख्याल से ही मैंने इसे ज्यादा चौड़ा और गढ़ा बना दिया है। आपने कहा था न कि लिंग घर के लिए चाहिए। इस गढे से पानी छलकने न पावेगा।''

चीतू ने लिंग के चारों ओर के गढे में उंगली में घुमाकर कहा।

''अबे उल्लू। यह पानी बहने का गढा नहीं है। इसका अर्थ है अर्थ।'' सेठ दांत पीसकर बोला।

मालिक हम मूर्ख मानुष, अर्थ क्या जानें। बस शिवलिंग ऐसे ही बनता है सो बना भर देता हूं। अब अर्थ समझना आपका काम। यह भी अच्छा ही है मालिक। ले जाकर एक बार आजमाइए तो। खराब नहीं होगा विश्वास रखिए।'' चीतू ने चिरौरी की।

''बेहूदा! इसको आजमाना क्या है। इतना पतला लिंग बनाकर ढक्कन जैसा भग बना दिया–कुछ मतलब निकलता है इससे।'' सेठ ने अत्यंत क्रोध में कहा।

चीतू को समझ में नहीं आया कि सेठ गढे को लेकर क्यों चीख रहा है, जबकि लिंग ठीक ही बना हुआ है। सेठ भग–भग क्या बोल रहा है यह भी चीतू को समझ नहीं आया। उसने अपनी गलती जाननी चाहिए। सेठ से कहा– ''आपने लिंग बनाने को कहा था– लिंग तो ठीक ही है। यह भग क्या है ? कैसा होना चाहिए था इसे ?''

''कहते हो, हम कलाकार हैं, इतना भी नहीं जानते ? यह लिंग शिवजी का लिंग है और यह पार्वती जी का भग–इतना भी नहीं जानते तो शिवलिंग क्या बनाते हो खाक ?'' सेठ चाहा कि इस बेवकूफ मूर्तिकार को आसान शब्दों में समझा दें, लेकिन लिंग भग की जगह कोई अन्य शब्द निकालने में उसकी जीभ ऐंठ गई। लेकिन सेठ ने लिंग के चारो ओर कुछ इस तरह से उंगली घुमाकर कहा कि नासमझ चीतू भी समझ गया।

लिंग–भग का अर्थ जानकर चीतू अवाक् रह गया। उसने अपनी नजर सेठ से हटा ली। बड़ा अजीब–सा लगा चीतू को। वह बड़बड़ाया – ''बस्साला! हम समझते थे इ कोई भगवान का मूर्ति–उर्ति है। हमको क्या पता इ किसी का गुप्तांग बेचकर पेट पालना घोर पाप हुआ। यमराज साला जूता मार–मार कर नरक में ढकेलेगा। थू ! साला आज से जो हम इसके नाम पर छेनी–हथौड़ी उठावें तो मादरचोद।

शिवलिंग नापसंद था। उसे पटक कर सेठ जा चुका था। शिवलिंग औंधा पड़ा था। चीतू ने बड़े कौतूहल से शिवलिंग देखा मानों पहली बार देखा हो।

उसने हथौड़ा उठाकर शिवलिंग पर मारा 'ठांय।' टूटे बिखरे शिवलिंग को देखकर चीतू उठाकर हंस पड़ा।

(साभार–बैकवर्ड)

पेज 1 का शेष ...

शिक्षा के व्यवसायीकरण के विरोध में 8 सितंबर को राष्ट्रीय सम्मेलन

गया है, जिससे सर्वाधिक प्रभाव इन्हीं वर्गों पर पड़ेगा। 1986 में संसद की सहमति से 10+2+3 की शिक्षा नीति बनी थी जिसे दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति ने उलट दिया। चूंकि इन्होंने अमीरों के लिए एवं निजीकरण बढ़ाने के लिए किया, इसलिए अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की बात तो दूर, बल्कि पुरजोर समर्थन मानव संसाधन मंत्रालय से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय ने दिया।

दुर्भाग्य है कि इस देश में शिक्षा को लेकर राजनैतिक लोग गंभीर नहीं हैं। जिस दिन शिक्षा जैसे मुद्दे पर चुनाव होगें, उस दिन भारत की दशा और दिशा बदलने लगेगी। ज्वाइंट ऐक्शन फ्रंट फॉर डेमोक्रेटिक एजुकेशन (एससी/एसटी/ओबीसी/लेफ्ट) का निर्माण दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा लागू किए गए चार वर्षीय पाठ्यक्रम को रोकने के लिए हुआ था लेकिन धीरे–धीरे महसूस किया गया कि यह बड़ा षडयंत्र है, लड़ना आसान नहीं है, इसलिए आंदोलन का दायरा देश स्तर तक बढ़ाना पड़ेगा। दिल्ली विश्वविद्यालय में लगभग 4500 शिक्षकों के पद खाली हैं, जिसे मुख्य रूप से दलितों व पिछड़ों से ही भरा जाना है। इन मुद्दों पर हम संघर्श कर रहे हैं, लेकिन अब तय किया गया है कि देश स्तर पर आंदोलन चलाया जाए। इसीलिए आगामी 8 सितंबर, 2013 (रविवार) को स्पीकर हॉल, कांस्टीट्यूशन क्लब, नई दिल्ली में 9 घंटे का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें शिक्षक, बुद्धिजीवी एवं सामाजिक कार्यकर्त्ता पूरे देश से आमंत्रित किए जा रहे हैं। मुख्य मांग है कि समान शिक्षा हो, अर्थात् जो शिक्षा उद्योगपतियों, मंत्रियों व नौकरशाहों के बच्चों को मिल रही है, वही 4 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को दी जानी चाहिए। पहले प्राइमरी षिक्षा का निजीकरण तेज हुआ था, अब उच्च षिक्षा का भी हो रहा है, इस पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। यह मांग सर्वथा उचित है और जो लोग यह कहते थक नहीं रहे हैं कि चार वर्ष का स्नातक कार्यक्रम अमेरिका में भी है तो वे यह भी जान लें कि वहां पर सरकारी एवं निजी क्षेत्र में शिक्षा के स्तर में कोई अंतर नहीं है, बल्कि सरकारी स्कूल बेहतर शिक्षा देते हैं। पूरा दिन बहस करने के बाद जो निष्कर्ष निकलेगा उस पर राष्ट्रीय आंदोलन चलाया जाएगा। 2014 के लोक सभा चुनावों के आते–आते यह मुद्दा इतना ताक़तवर बन जाए कि सभी दल इस पर चुनाव लड़ें। शुरुआत में निम्न संगठनों से यह गठित हुआ है, लेकिन आगे चलकर और सैकड़ों हजारों संगठनों को समाहित किया जाएगा। जिन संगठनों से इसकी शुरूआत हुई है वे हैं – इंदिरा अठावले, विनोद कुमार (अनुसूचित जाति, जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ), डॉ0 हैनी बाबू (ए.एस.जे.), विजया वेंकटरमन, डॉ0 शास्वती मजूमदार एवं आभा देव (डी. टी.एफ.), प्रेम सिंह (एस.टी.ए.), डॉ0 एस.के. सागर (एफ. ओ.सी.यू.एस.), डॉ0 केदार कुमार मंडल (ए.एफ.एस.जे.), डॉ0 नंदिनी दत्ता (सी.टी.एफ.), डॉ0 हंसराज सुमन (एफ.ए. एस.जे.), पाल दिवाकर (एन. सी.डी.एच.आर.) पी. अब्दुल नजर (सी.एफ.आई), हर्षवर्धन दवने, दिनेश अहिरवार, (एन. एस.ओ.एस.वाई.एफ.) विनय भूषण (ए.आई.बी.एस.एफ.), अनूप पटेल (एस.यू.आई.), लेनिन विनोबर (एस.एस.जे.), डॉ0 कौशल पवार, प्रो0 हेमलता महेश्वर, डॉ0 सुकुमार, जी.एन. साईंबाबा, आदि।

जिन–जिन साथियों को इस संबंध में सूचना मिले, वे फौरन शिक्षा से संबंधित लोगों से संपर्क करके सम्मेलन में आने के लिए प्रेरित करें। साथ ही साथ उनके बारे में अग्रिम सूचना भी दें। अगर पूछा जाए कि देश में वे प्रमुख कारण कौन हैं तो वह है शिक्षा का व्यवसायीकरण। अभी तक तो गनीमत है और आम लोग भी शिक्षा प्राप्त कर पा रहे हैं लेकिन निजीकरण के बाद यह असंभव हो जाएगा। अशिक्षित समाज अपने मान–सम्मान एवं प्रगति के बारे में सोच भी नहीं पाता। इसलिए देश के सभी प्रगतिशील लोग दलित, आदिवासी, पिछड़े और अल्पसंख्यक एक होकर के इस सम्मेलन को सफल बनाने के लिए भाग लें।

संयोजक
डॉ0 उदित राज,
राष्ट्रीय अध्यक्ष
अजा/जजा परिसंघ

पेज 1 का शेष ...

बोधगया पर आतंकी हमले की निंदा-उदित राज

जानी जाती है, की जितनी निन्दा की जाए कम हैं। अग्रिम में जब सूचना मिल गयी थी तो हमले को रोका जाना मुश्किल नहीं था।

डॉ0 उदित राज अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बौद्ध नेता है और उनके नेतृत्व में 4 नवंबर 2001 को लाखों लोग बौद्ध बने थे, जिसको न केवल भारत में जाना जाता है बल्कि दुनिया के कोने–कोने में। उन्होंने दुख जताया कि राजनीतिक लाभ के लिए लोग सरकारी एजेंसियों की अग्रिम सूचना पर भी संदेह कर रहे हैं, जो देश के लिए ठीक नहीं है। माना कि एजेंसियां हमेशा सही नहीं होती लेकिन जब पूर्व में किसी घटना की सूचना दी गयी तो उस पर विश्वास करना ही पड़ेगा। न विश्वास करना या हल्के में लेने का मतलब कि भारी कीमत चुकाना और यही बोधगया के मामले में हुआ है। 08 जुलाई को टी–22 अतुल ग्रोव रोड, नई दिल्ली–110001 पर बौद्ध समुदाय की एक आवश्यक बैठक हुई, जिसमें इस घृणित कृत्य की घोर निंदा करते हुए मांग की गयी कि जल्द से जल्द दोषियों को पकड़कर उचित सजा दी जाए। यह भी मांग की गयी कि बोधगया की सुरक्षा फौरन सीआईएसएफ को सुपुर्द की जाए। यह न केवल बौद्ध धर्म पर हमला है बल्कि बिहार में आ रहे पर्यटकों को हतोत्साहित करने का काम किया गया और उसका असर बिहार की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा।

डॉ0 उदित राज लॉर्ड बुद्धा क्लब एवं बुद्धा एजुकेशन फाउंडेशन के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होनें कहा कि बोधगया में कानून–व्यवस्था की बहुत ही हालत खराब है। आए दिन पर्यटकों के साथ मारपीट और लूट–पाट होती ही रहती है और विदेशी मिशन पर हमला, चोरी और डाका भी पड़ता है। वहां पर रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से न केवल आतंकी वारदात को अंजाम आसानी से दिया जा सकता है बल्कि और भी दुर्घटना हो सकती है। यदि रोशनी की समुचित व्यवस्था होती तो शायद 7 जुलाई की घटना को टाला जा सकता था। वहां का रख–रखाव बिल्कुल उचित नहीं है।

पाठकों से अपील

'वॉयस ऑफ बुद्धा' के सभी पाठकों से निवेदन है कि जिन्होंने अभी तक वार्षिक शुल्क/शुल्क जमा नहीं किया है, वे शीघ्र ही बैंक ड्रॉफ्ट द्वारा 'जस्टिस पब्लिकेशंस' के नाम से टी–22, अतुल ग्रोव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001 को भेजें। शुल्क 'जस्टिस पब्लिकेशंस' के खाता संख्या 0636000102165381 जो पंजाब नेशनल बैंक की जनपथ ब्रांच में है, सीधे जमा किया जा सकता है। जमा कराने के तुरंत बाद इसकी सूचना ईमेल, दूरभाष या पत्र द्वारा दें। कृपया 'वॉयस ऑफ बुद्धा' के नाम ड्राफ्ट या पैसा न भेजें और मनीआर्डर द्वारा भी शुल्क न भेजें। जिन लोगों के पास 'वॉयस ऑफ बुद्धा' नहीं पहुंच रहा है, वे सदस्यता संख्या सहित लिखें और संबंधित डाकघर से भी सम्पर्क करें। आर्थिक स्थिति दयनीय है, अतः इस आंदोलन को सहयोग देने के लिए खुलकर दान या चंदा दें।

सहयोग राशिः

पांच वर्ष : 600 रुपए

एक वर्ष : 150 रुपए

क्या वे जमीनी हकीकत को समझते हैं जो कहते हैं कि जातिवाद खत्म हो गया?

दलित युवक का शव सुरक्षित रखा जाए- हाईकोर्ट

चेन्नई (भाषा)। मद्रास हाईकोर्ट ने 5 जुलाई को तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया कि वह दलित युवक इलावरासन का शव 9 जुलाई तक सुरक्षित रखे। साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि मृतक के पिता को पोस्टमार्टम रिपोर्ट की एक प्रति और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया का वीडियो सौंपा जाए। इलावरासन धर्मपुरी में रेल पटरी के पास मृत पाया गया था। इस बीच तमिलनाडु के राजनीतिक दलों ने भी इलावरासन की मौत पर दुःख जताते हुए इस पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है।

न्यायमूर्ति वी. धनपालन और न्यायमूर्ति सीटी सेल्वम ने यह आदेश अधिवक्ता शंरासुब्बू के उस अनुरोध पर दिया जिसमें कहा गया था कि जब डाक्टरों का दल पोस्टमार्टम करे तो इलावरासन के माता–पिता की पसंद के एक डाक्टर को वहां मौजूद रहने की इजाजत दी जाए। सरकारी वकील षणमुगावेलायुतम ने कहा कि चार घंटे की प्रक्रिया दिन में 11 बजे खत्म हो गई। इस पर वकील ने आपत्ति की और कहा कि उन्होंने जिला पुलिस अधीक्षक को सूचित किया था कि मामला अदालत में उठाया जाएगा और उन्हें बताया गया था कि पोस्टमार्टम साढ़े 11 बजे ही किया जाएगा। इन बयानों के बाद न्यायाधीशों ने संबंधित अधिकारियों को शव 9 जुलाई तक सुरक्षित रखने का निर्देश दिया।

इससे पहले सुबह न्यायमूर्ति आर. बानुमति और न्यायमूर्ति टीएस शिवाज्ञानम ने दलित विरोधी हिंसा और आगजनी व पीड़ितों को मुआवजा देने से संबंधित जनहित याचिकाओं पर सुनवाई 19 जुलाई तक स्थगित कर दी है।

मालूम हो कि एक सवर्ण लड़की के साथ इलावरासन के शादी करने को लेकर पिछले साल नवंबर में जिले के तीन गांवों में दंगे भड़क गए थे। इलावरासन का शव 4 जुलाई को रेल पटरी के पास मिला था। इससे एक दिन पहले ही उसकी पत्नी दिव्या ने कहा था कि वह उसके पास कभी वापस नहीं जाएगी। इसके कुछ ही घंटे बाद इलावरासन रेल पटरी के पास मरा मिला।

मां की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर मद्रास हाईकोर्ट में पेशी पर दिव्या ने कहा था कि वह लगातार दबाव में थी और अपने पिता को भूल नहीं पा रही है जिन्होंने उसकी शादी के मुद्दे पर खुदकुशी कर ली थी।

इलावरासन की मौत से नैकेनकोट्टाई गांव में तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई है। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है और संवेदनशील क्षेत्रों में हथियारबंद पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं।

इस दलित युवक की मौत के मामले में तमिलनाडु के राजनीतिक दलों ने भी चिंता जताई है और मामले में उपयुक्त जांच की मांग की है। माकपा ने इलावरासन की मौत पर दुख और चिंता जाहिर करते हुए कहा कि अपने से ऊंची जाति की लड़की से शादी करने की उसने कीमत चुकाई है। पार्टी की राज्य इकाई के सचिव जी. रामाकृष्णन ने कहा कि अपने पति से अलग होने के लड़की के फैसले को 'जातिगत, सामाजिक बाध्यता' के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस दलित युवक की मौत से कई सवाल खड़े हो गए हैं। एक बयान में माकपा नेता ने कहा कि सरकार और पुलिस को इस मामले में जांच करनी चाहिए और सच्चाई का पता लगाना चाहिए।

दिव्या व इलावरासन

इलावरासन की मौत पर शोक जताते हुए एमडीएमके के नेता वाईको ने कहा कि शादी के बाद दोनों समुदायों के बीच तनावों के कारण उसकी पत्नी दिव्या ने उससे संबंध तोड़ने का फैसला किया। उन्होंने मौत की न्यायिक जांच कराने और लड़की की पर्याप्त सुरक्षा देने की मांग की।

भाजपा राज्य इकाई के अध्यक्ष पी राधाकृष्णन ने कहा कि सरकार को विभिन्न समुदायों के प्रमुखों की बैठक बुलानी चाहिए ताकि सामाजिक सौहार्द्र सुनिश्चित की जा सके। पार्टी ने इलावरासन की मौत की जांच की भी मांग की।

(साभार–जनसत्ता)

बहुजन नायक मान्यवर 'उदित राज'

डॉ. लाल रत्नाकर

मनुवादी–मायावादी जातिवादी ब्राह्मण भाई दलित भले ही गुमराह करे पर यदि कोई नव–बुद्धिस्ट सत्य में मानवतावादी लार्ड बुद्धा और भारत रत्न बाबा साहेब डॉ अम्बेडकर की सत्य का साथ देने की नसीहत को मानता हैं तो बाबा साहेब के बाद जितना काम दलित–बहुजन के लिए बहुजन नायक मान्यवर डॉ उदित राज (जो न तो विधायक है न सांसद) ने किया, उतना करने वाला बिरला एक बाबा साहेब के बाद दलित पैदा कर नहीं पाए। हिन्दू धर्म की बेड़ियाँ तो लोगों को बुद्धिवादी बनाने का सबसे बड़ा काम भी बाबा साहेब के बाद डॉ उदित राज ने ही किया और आज तक भारत में बुद्ध की विचारधारा के संरक्षक के रूप में संघर्ष कर रहे हैं पर कोई भी दलित अपनी जाति का चश्मा उतार कर बहुजन नायक मान्यवर डॉ उदित राज को नहीं देखता। ऐसी खबरे मिली है कि परिस्थिति को समझने वाला बुद्धिजीवी दलित तबका धीरे–धीरे डॉ० उदित राज को संसद (लोकसभा या राज्यसभा) में पहुंचाने के लिए लामबंद होकर, डॉ उदित राज को मनुवादी–मायावाद के अंत के बाद विकल्प के रूप में देख रहा है।

प्रसंगवश,

आदरणीय शर्मा जी, आपका आलेख यद्यपि 'चापलूसी से ओत–प्रोत होते हुए भी सत्य' है पर आपकी कथा में बाबा साहब और मान्यवर डॉ. उदित राज की तुलना करने का कोई प्रसंग ही नहीं बनता यह तो एक तरह से द्विज सोच का सरोकार है जबकि डॉ. उदित राज जी का सामाजिक भेदभाव के खिलाफ अधूरे पड़े बौद्धिक चिंतन का संकल्प लेना उस समाज के लिए एक महान समर्पण है। हजारों सालों में ऐसे लोग जन्म लेते हैं, पर सदियों से ये दलित व पिछड़े 'आकर्षण' के शिकार रहे हैं जो अब और मदहोश हो गए हैं। इनमे 'बौद्धिकता' कहाँ से आएगी। जिस समाज को बाबा साहब ने हक दिलाने के लिए जो बहस आरम्भ की, उस क्रम को जारी रखने का दायित्व भी इन्होंने उठा रखा है। फिर ये बात मैं बहुत ही मजबूती से कह पा रहा हूँ कि वह जिस उक्त समाज का हित करना चाहते हैं वह उक्त समाज भी आज सामाजिक गिरावट के वशीभूत हो उन्हीं उचक्कों के पीछे–पीछे दौड़ रहा है। उसे ही नेता मान रहा है जिन्हें बौद्धिक रूप से इस समाज के विकास की कोई तकनीक ही नहीं मालूम है कि इनका असली उत्थान कैसे होगा। मुझे पता है कि डॉ. उदित राज के मन में जो संकल्पना इस समाज के लिए है, शायद ही किसी भी नेता के इर्द–गिर्द भी हो। पर एक बात और कहूँ जिस संसद की बात करके आप डॉ. उदित राज जी को बौना कर रहे हैं, उसमें बेनी प्रसाद वर्मा से लेकर तथाकथित नेताओं का और साम्राज्यवादियों का पूरा कुनबा परिवार विराजमान है, जैसे वह संसद न होकर कोई आरामगाह हो। अब ऐसी जगह में उनकी उपस्थिति मात्र की सोचना और 'आपकी तरह' से उसकी परिकल्पना करना डॉ. साहब का अपमान करने जैसा है। इनके पास बड़ा विकल्प है जिसकी भविष्य में जरूरत है। यह विश्वरुपी 'वैश्विक संसद' के हिस्से हैं जिससे दलितों +पिछड़ों+अन्य वंचितों = असली भारतीय के भविष्य और सामाजिक बदलाव का सपना है शर्मा जी, अतः आप अपने ओछे आचरण से लोगों में भ्रम न उत्पन्न करें, इसी में आप का भी भला होना है। अन्यथा केवल संसद तक की इनकी अप्रोच होती तो इन्हें संसद तक पहुंचने में कब की सफलता मिल चुकी होती। – (क्षमा याचना सहित यदि आपको कहीं लगे की आपकी अवमानना की गयी है शर्मा जी)

धर्म और शिक्षा से भी ऊपर जाति

डॉ. उदित राज

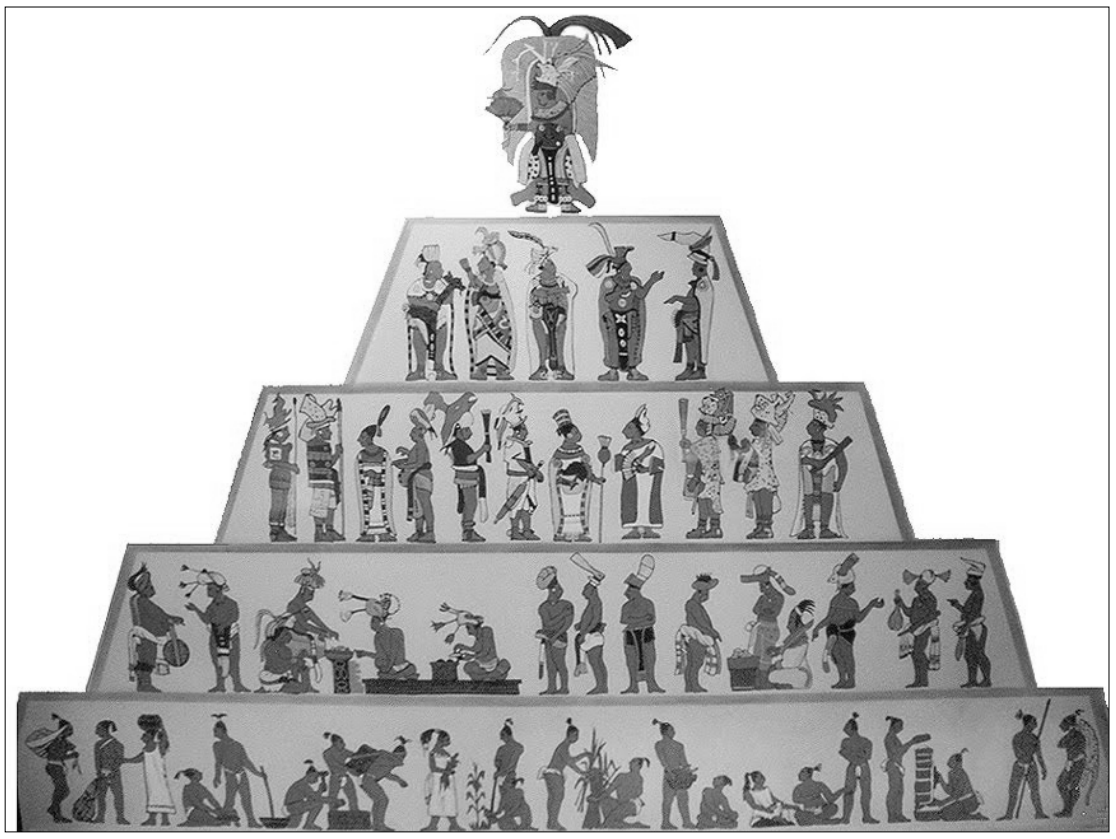

5 जुलाई, 2013 को तालकटोरा स्टेडियम, नई दिल्ली में जब अखिल भारतीय जाट महासभा का सम्मेलन सुना तो कुछ हैरानी की बात थी कि हरियाणा और पंजाब में लगातार राजनैतिक सत्ता इनके पास है फिर भी अपने को वंचित महसूस कर रहे हैं। इससे ज्यादा और हैरानी तब हुई जब विदेश में पढ़े और हिन्दू धर्म को छोड़कर बने सिक्ख, कैप्टन अमरेन्दर सिंह का राष्ट्रीय अध्यक्ष होना। जो लोग शहरी पढ़े–लिखे बात करते हैं कि जाति तो पुराने जमाने की बात हो गयी है अब वे अपनी समझ को दुरूस्त कर लें। कैप्टन अमरेन्दर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री रहे हैं, राजघराने से आते हैं, उच्च शिक्षा तो प्राप्त कर ही चुके हैं और पूर्वजों के धर्मांतरण के बावजूद जाति के घेरे से नहीं निकल पाए तो यह सोचना कि जाति व्यवस्था कहीं से कमजोर हुई है, दिन में सपने देखने के समान है। जैसे–जैसे लोगों की जानकारी बढ़ती जा रही है, मान–सम्मान का महत्त्व समझ में आता जा रहा है और भागीदारी का क्या मतलब है? वैसे–वैसे वंचित और सोई हुई जातियां भी हिस्सा मांगने के लिए आगे आती जा रही हैं और यह जातिवाद नजर आता है। यदि जाति इस देश में न होती तो दुनिया का महाशक्तिशाली अमरीका न होकर भारत होता, क्योंकि यहां की जलवायु, दिमाग, आबादी आदि औरों की तुलना में बेहतर है।

किसी संस्था से इतना लाभ नहीं मिलता जितना जाति से तो ऐसे में काहे को कोई जाति छोड़ेगा। जैसे ही आदमी जन्म लेता है, उसका बीमा हो जाता है। अनोखी बात यह है कि इस बीमा पर कोई किस्त नहीं अदा करनी पड़ती और सामाजिक, मानसिक, आर्थिक लाभ लगातार मिलता रहता है। जाति के इतने फायदे हैं कि उतने कोई और संस्था दे ही नहीं सकती। इसके सामने तो राजनीतिक लाभ नहीं के बराबर है। जाति की वजह से खान–दान चलता है। शादी, बच्चे एवं सेक्स की गारंटी है। मरने–जीने पर सबसे पहले जाति ही काम आती है। जाति के वोट से ही सत्ता की प्राप्ति कहीं ज्यादा संभव है। सामाजिक और मानसिक सुरक्षा सुनिश्चित है। जब तक जाति है, तो ये फायदे मिलते रहेगें। जाति टूटेगी तो ये लाभ अपने आप समाप्त हो जाएंगें। तभी जातीय भावना से ऊपर उठा जा सकता है।

जो राष्ट्रभक्ति की रट लगाते थकते नहीं वे अपने अंदर झांककर देखें कि कितनी सतही समझ उन्हें समाज के बारे में है। भले ही ये अच्छी भावना के साथ राष्ट्रभक्ति का नारा देते हैं लेकिन सतही समझ की वजह से वास्तव में उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। बड़े शहरों में जो विशेषकर अंग्रेजी माध्यम से उच्च शिक्षा प्राप्त किए हैं, वे ज्यादा कहते हैं कि जाति बीते हुए काल की बात है, लेकिन अपने अंतःकरण में झांककर ईमानदारी से देखें तो कुछ और ही बात मिलेगी। ये लोग ज्यादा उन नेताओं को जातिवादी कहते हैं, जो 80 के दशक के बाद जाति के सहारे राजनैतिक सत्ता में भागीदारी लिए। जो सदियों से जाति व्यवस्था का लाभ लेकर स्थापित हो चुके हैं, उन्हें इसके सहारे की अब जरूरत ही नहीं रह गयी। यदि जाति का सहारा खुले तौर पर लेंगे तो घाटे में जा पड़ेंगे क्योंकि ये अल्पसंख्यक हैं। मैंने तो कई बार ऐसे लोगों से पूछा कि मानता हूं कि आप जाति में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन बताएं कि उनके मां–बाप, भाई–बहन एवं रिश्तेदार शादी क्या जाति के बाहर किए? तो सीधा जवाब मिलता नहीं और कई बार झल्ला भी पड़ते हैं। अपवाद में हुई अंतर्जातीय शादी का उदाहरण देकर सवाल का जवाब दे डालते हैं। इनसे और आगे पूछे कि अंग्रेजी अखबारों के वैवाहिक कॉलम को क्या देखते व पढ़ते हैं, जिसमें ज्यादातर सवर्ण शिक्षित लोगों का विज्ञापन होता है, अपवाद को छोड़कर जाति में ही शादी की मांग होती है। तथाकथित उच्च शिक्षा प्राप्त लोग इससे अपने ज्ञान और समझ को दुरूस्त कर लें, तब जाकर राष्ट्रीयता के मिशन को आगे बढ़ा भी सकते हैं। जब तक हम रोग को मानेगें नहीं तो इलाज कैसे किया जा सकता है?

जब अन्ना हजारे का अनशन अगस्त 2011 में ऊंचाई पर था तब भी हमने आवाज उठायी थी कि आर्थिक भ्रष्टाचार सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक पहलू की देन है। जब भगवान को रिश्वत दिए बिना लोग नहीं मानते तो इंसान इसका लेन–देन आपस में क्यों नहीं करेगें? मंदिर और पूजा के समय कुछ न कुछ आदमी चढ़ावा, जैसे – चुंनरी, नारियल, अगरबत्ती, कपड़ा, मिठाई, फल आदि करके ही, आर्शीवाद और लाभ की कामना करते हैं। कहीं–कहीं तो मुर्गा, बकरा, दारू, गांजा तक चढ़ाया जाता है। अमीर लोग सोना–चांदी और हीरे–जवाहरात अर्पण करते हैं। इन परिस्थितियों में क्या संभव है कि स्वतः या बिना दबाव के आम आदमी ईमानदार रह सकता है। इस बात को अन्ना हजारे को मैंने 2012 में समझाने की कोशिश की। एक बैठक में उनसे मुलाकात हो गई और मैं पूछ बैठा कि सन् 2011 की तुलना में 2012 में भ्रष्टाचार बढ़ गया (उस समय के ट्रांस्परेंसी इंटरनेशनल सर्वे के अनुसार) । उन्होंने जवाब में कहा कि भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए देश के गांव–गांव में जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि एक गांव जहां वे रहते हैं को सुधारने में वे पूरी जिंदगी लगा दिए तो 6,38,588/– गांवों तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? इसका जवाब वे क्या देते?

जो लोग मेरिट की वकालत करते हैं, वे जान लें कि जाति की वजह से इस देश में मेरिट की परंपरा पड़ी ही नहीं। सवर्ण जाति में जन्म लेने से ही आदमी योग्य मान लिया जाता है। मेरिट जन्मना के आधार पर अभी तक तय होती रही है और इसी कारण देश गुलाम हुआ। इसी आधार पर ज्ञान और बुद्धि। क्षत्रियों को ही शासन–प्रशासन चलाने की जिम्मेदारी थी, इसमें कोई मेरिट तो नहीं है बल्कि जाति पर आधारित है और यही कारण है कि सिकंदर के हाथों परास्त हुआ भारत 1947 के पहले तक लगातार हारता ही रहा। हारने का कारण चाहे जो भी बताया जाए जैसे – दुश्मन की धोखेबाजी, आधुनिक औजार का उपयोग, आपसी फूट, जलवायु का प्रतिकूल होना आदि–आदि, लेकिन यह सब थोथी बात है। वास्तव में जाति ही रही इसके मूल कारण में। हजारों वर्षों से जिस जाति को गंदगी साफ करने का व्यवसाय दिया गया तो क्या वह मेरिट के आधार पर है? इस देश में सबसे बड़ी दो समस्या है, एक है जातिवाद तो दूसरा है स्त्री और पुरुष की साझेदारी का अभाव और यह मूलतः जाति व्यवस्था की ही देन है। जो लोग सरकारी नौकरियों में आरक्षण का विरोध करते हैं, वे गंदगी साफ करने और चमड़े आदि का पेशा जो जाति के आधार पर आरक्षित है का विरोध करके क्यों नहीं उसमें भागीदारी की बात करते? जिस आरक्षण से वंचितों का लाभ हो, उसका विरोध तो है और जिससे वे कमतर देखे जाते हों तो उसका क्यों नहीं?

कुछ लोग जाति को बहुत खराब तो मानते हैं, लेकिन मिटाने का काम नहीं करते हैं और कुछ लोग चेतना के स्तर पर नहीं लेकिन अचेतन की स्थिति में इस भावना से ग्रसित रहते ही हैं। भले ही एक तबका जाति व्यवस्था के माहौल से ऊपर उठकर आधुनिकता के माहौल में पढ़–लिखकर सोचे कि वह जाति से मुक्त हो गया है, अधूरा सत्य है। सैकड़ों हजारों सवर्ण लड़कियां अल्पसंख्यकों से प्यार और शादी करती हैं तो न उनका बहिष्कार होता है, न ही जान से मारने का प्रयास किया जाता है, लेकिन जब वही दलितों और पिछड़ों के साथ करती हैं तो समाज सहन नहीं कर पाता। अंतर्धामिक शादी हो इसमें क्यों कोई विरोध करे और फिल्म जगत का उदाहरण से हम समझ और देख सकते हैं। आधुनिक लड़के–लड़कियां आरक्षित वर्ग को कमतर देखती हैं और उसका कारण है कि जो उन्हें सवर्ण जाति में पैदा होने का लाभ मिलता था उसमें हिस्सेदारी आरक्षण की वजह से तथाकथित निम्न जातियों की भी हो गयी। दूसरा बचपन से ही मां–बाप या जाति–बिरादरी से तथाकथित नीची कही जाने वाली जातियों के बारे में सुनते हैं कि ये गंदे होते हैं, कम पढ़–लिखकर भी अधिकारी हैं, इनके कारण स्कूल–कॉलेज से लेकर तमाम अन्य क्षेत्रों में दक्षता पर असर पड़ता है। और यही भावना संस्कार के रूप में विकसित हो जाती है और जिससे उन्हें नीच और अयोग्य समझते हैं। जब जाति टूटेगी तभी इसका फायदा भी कम होगा और उसी परिस्थति में लोग जातीय भावना से ऊपर उठ सकते हैं, वरना असंभव है।

25 नवंबर को दिल्ली में राष्ट्रीय रैली

हक बिना मांगें मिलता नहीं। कभी–कभी छीनना भी पड़ता है। हम छीनने की स्थिति में तो नहीं हैं, लेकिन अपनी मांग को लेकर दबाव जरूर बना सकते हैं। अतीत में ऐसा हो चुका है, जिसके परिणाम बहुत ही अच्छे रहे हैं। कुछ मांग ऐसी होती है, जिसको छीनना ही पड़ता है। निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग कोई आसान नहीं है। इस समय देश को चलाने में राजनैतिक ताक़त अकेले नहीं रह गयी है बल्कि कारपोरेट घरानों की भूमिका भी अहम हो गयी है। देश में कौन सी बात जरूरी है, किस पर बहस चलनी चाहिए, यह सब कारपोरेट घराने मीडिया के द्वारा तय करते हैं। निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग इन्हीं से है और ये क्यों इसकी खबर बनने देगें ? लगातार सरकार पर भी दबाव बनाए हुए हैं कि वह हमारी बात को न माने। इसका एक ही जवाब है कि पूरे देश के दलित एवं आदिवासी अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ के बैनर के नीचे एक होकर आगामी 25 नवंबर को रामलीला मैदान, नई दिल्ली में एकत्रित होकर संसद का घेराव करें।

निजीकरण को रोकना हो या इस क्षेत्र में भागीदारी की बात हो, इसका संघर्ष दिल्ली में ही करना पड़ेगा। हाल में मेरा मुंबई यूनिवर्सिटी में जाना हुआ तो जब बात किया कि दिल्ली विश्वविद्यालय में किस तरह से उच्च शिक्षा को अमीरों तक सीमित करने का षड्यंत्र चल रहा है तो सीनेट के सदस्य ने कहा कि महाराष्ट्र में तो उच्च शिक्षा के लिए अलग कानून है। उनका कहना था कि जो दिल्ली विश्वविद्यालय में हो रहा है, यह यहीं तक सीमित रहेगा। यह भ्रांति है। भूमण्डलीकरण एवं निजीकरण के दौर में पहले जो विश्व स्तर पर घटना घटित होती है, वह दिल्ली पर असर करती है और उसके बाद निचले स्तर तक जाता है। भले ही महाराष्ट्र का यूनिवर्सिटी एक्ट अलग हो लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय की नीति, यदि रोकी नहीं गयी, का प्रभाव पूरे देश में पड़ना स्वाभाविक है। मान लिया जाए कि मुंबई यूनिवर्सिटी इस नीति को नहीं मानती तो निजी क्षेत्र में दर्जनों विश्वविद्यालय चार वर्ष के स्नातक कार्यक्रम को लेकर आ जाएंगें और रोजगार मिलने की ज्यादा संभावना की लालच में छात्र वहां पर प्रवेश लेना शुरू कर देगें। ऐसे में यह विश्वविद्यालय अलग–थलग पड़ जाएगा। केन्द्र सरकार से तमाम सहायता राज्य सरकारों को लेना ही पड़ता है, वह तभी मिलेगी जब उसकी नीति को भी स्वीकार किया जाएगा। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन देश में उच्च शिक्षा का मानक तय करने की संस्था है, यह पैसा भी देती है। क्या इससे केन्द्र की नीति नहीं नीचे तक लागू हो जाएगी ? हरियाणा हो या जम्मू–कश्मीर या और कोई प्रदेश वहां पर जो स्थानीय समस्याएं हैं, वह कहीं–नहीं केन्द्र सरकार की नीति से भी संबंधित हैं। इसलिए इस समय सारी ताक़त केन्द्र पर लगनी चाहिए।

जिस पदोन्नति के आरक्षण की समस्या का समाधान आप लोगों के सहयोग से सन् 2001 में हो गया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी 2006 में वैध घोषित किया, वह फिर से उ0 प्र0 सरकार की कमी की वजह से खड़ा हो गया है। पदोन्नति में आरक्षण देने का विधेयक लोक सभा में लंबित है और भारी दबाव बनाकर ही इसे पास कराया जा सकता है। जो कर्मचारी–अधिकारी अभी सुस्त एवं उदासीन पड़े हैं, उनकी गर्दन पर भी यह तलवार लटक सकती है। इसलिए वे भी पूरे तन–मन और धन से साथ दें। सरकारी विभागों का निजीकरण बढ़ रहा है, जिसका सबसे ज्यादा शिकार बाल्मीकि समाज हुआ है। इसके बावजूद यह समाज आंदोलित नहीं हो रहा है, यह बड़ी निराशा की बात है। अभी से पूरी गंभीरता से इस रैली की सफलता के लिए तैयारी शुरू कर दी जानी चाहिए।

- डॉ0 उदित राज, राष्ट्रीय अध्यक्ष

Rest of Page 7 ...

Caste is Even Above Religion and Education

to gain anything is not opposed?

Some people, of course, take the caste system as the bane of the society but do not take any steps to remove it and some people not consciously but unconsciously suffer from this mindset. Maybe, one set of people because of their modern educational background think that they have risen above the caste mind-set but it is only half-truth. Hundreds and thousands of upper caste girls fall in love with boys from the minority community and ultimately marry them but they are neither ostracized nor killed but when the upper caste girls make love or marriage with Dalits and backwards, then their society does not tolerate it. In the film industry, inter-religious marriages are a commonplace happening. Modern boys and girls from the upper caste who were earlier getting reservation in certain areas because of their caste tag, look down upon the SC/ST people who are getting the benefits on account of reservation in jobs etc. Secondly, from the very childhood, girls and boys listen from their parents or people of upper caste about the people belonging to SC/ST/OBC category who are considered dirty and become officers even though they are less qualified because of which efficiency is adversely affected in other areas. For this reason, they are considered low and inefficient. It is only when the shackles of the caste system are broken that we can rise above the caste feelings and everybody stand to gain otherwise it is impossible to bring any material change.

Appeal to the Readers

You will be happy to know that the **Voice of Buddha** will now be published both in Hindi and English so that readers who cannot read in Hindi can make use of the English edition. I appeal to the readers to send their contribution through Bank draft in favour of **'Justice Publications'** at T-22**,** Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001. The contribution amount can also be transferred in 'Justice Publications' Punjab National Bank account no. 0636000102165381 branch Janpath, New Delhi, under intimation to us by email or telephone or by letter. Sometimes, it might happen that you don't receive the Voice of Buddha. In that case kindly write to us and also check up with the post office. As we are facing financial crisis to run it, you all are requested to send the contribution regularly.

Contribution:
Five years : Rs. 600/-
One year : Rs. 150/-

Caste is Even Above Religion and Education

Dr. Udit Raj

When I heard about the All India Jat Maha Sabha Sammelan on 5.7.2013 at Talkatora Stadium, New Delhi, I was a little surprised to know that the Jats of Punjab and Haryana who have been a ruling class for a long time are feeling deprived. The bigger surprise was when I came to know that a foreign-educated Capt. Amarender Singh, who had adopted Sikhism after quitting Hinduism, is the President of the All India Jat Maha Sabha. The urban educated elite who think that caste is an out-dated concept may have to change their opinion after reading this report. Capt. Amarender Singh has been Chief Minister of Punjab and belongs to a royal family. Despite the fact that he is highly educated and his forefathers having converted to Sikhism, he is not able to come out of the caste grove. Under these circumstances, if anybody presumes that the shackles of the caste system are breaking, he is only day-dreaming. Gradually when awareness increases among people, they start realizing the importance of their self-respect and their rights and that is participation in governance all about. Thus, people of many castes who are deprived and are ignorant about their rights are coming forward and asking for their rights which looks like casteism. Had casteism not been the bane of our society, the most powerful country of the world would have been India and not America because of its better climate, intellect and population as compared to other countries.

No institution or organization gives greater benefit than a caste one. It is for this reason that nobody wants to get rid of his caste tag. As soon as a person is born, he is insured and the surprising thing is that no premium is required to be paid for this insurance and immediately you start getting social, intellectual and economic benefits. No other institution can give more benefits than a caste association. Even the political gains pale into insignificance as compared to the caste gains. It is because of the caste factor that a family is given a high status which gives them guarantee for marriage, children and sex. At the time of death or birth, it is the caste which matters must. Caste vote bank is more important for a political victory than any other factor. Social and emotional security is guaranteed. So long as there is the caste factor, the benefits will be immense. When the shackles of the caste system are broken, these gains will automatically end and it is only then we shall be able to rise above caste factor.

People who are never tired of bragging about patriotism should do some introspection and find out as to what is their knowledge about the society at the ground level. Even though they may be quite sincere about their thoughts of patriotism, but in reality they cannot realize their goals. In the big cities, people who have got higher education through English medium,are quite often heard of saying that caste system is a product of the by-gone ages, but if they do some honest introspection, it will be found that the reality is different. These people mostly call those leaders as casteist, who won the elections on the basis of caste. People who are firmly established by taking advantage of the caste system over the the centuries, do not require the help of caste system any more.If they openly take advantage of they caste system, they will stand to lose as they are in minority. I have quite often asked these people who claim that they do not believe in casteism whether their parents, brothers and sisters and other close relatives married outside their caste-fold.They simply replied in the negative and sometimes they felt offended. By quoting some exceptions of the inter-caste marriages, they only prove my point. If they are further asked whether they go through the matrimonial columns of English newspapers where most of the matrimonial advertisements are agiven by the uppter caste educated people. Barring exceptions, matrimonial proposals are invited by the advertiser from people of their own caste. The so-called urban intellectual class need to change their mind-set on this score and it is only then that the cause of nationalism can be taken forward.Unless we diagnose the disease, we cannot cure it.

When Anna Hazare's fast against corruption, in August 2011 was at its zenith, we had expressed the view that economic corruption is a byproduct of social, religious and cultural factors. When people do not hesitate to bribe God, then why should they not indulge in bribery among themselves. At the time of visiting temples or during various types of Pujas, people make some offerings like coconut, fruit, sweets, clothes and incense sticks and in turn expect blessings of God. At certain places, things like chicken, mutton, opium and whisky are also offered. The rich people offer silver, gold and diamonds. Under these circumstances, it is not possible to remove corruption voluntarily or through some coercive means. I tried to convince Anna Hazare in 2012 on this issue. During one of my meetings with him, I told him that according to a survey of the Transparency International, corruption in 2012 has increased as compared to corruption in 2011. His reply was that for removing corruption, we will have to go to each and every village. To this, my reply was that he had spent his life-time in removing corruption from just one village Ralegan Siddhi and how much time it will take to remove corruption from 6,38,53 villages. For this, he had no reply.

People who plead for merit, should know that because of the caste system, merit has never been a tradition in our country. By virtue of birth in a upper caste family, a person is considered meritorious. Birth in a particular upper caste family has been a criteria of merit, knowledge and intellect and it is precisely for this reason that the country has remained under slavery for centuries. Kshatriyas became the ruling class on the basis of caste for which there appears to be no justification. It is for this reason that ever since India's defeat at the hands of Alexander the Great, the country remained a slave till 1947 when we got Independence. We may attribute our defeat to so many factors like treachery of the enemy, use of modern weapons, divisive tendencies among ourselves, hostile climate etc, but these are all lame excuses. In fact, the main reason for this state of affairs is the caste factor. Is it because of merit that a caste which has been assigned the job of scavenging and night-soil carrying? Two biggest problems faced by the country are, casteism and sex segregation. Why do the people who are opposed to reservation in Govt. jobs, oppose or protest against the scavenging and tannery job which are reserved for certain people on caste basis. The reservation which is beneficial for the deprived people is opposed while the area in which they do not stand

Rest on Page 6 ...

Even in death, families shun two teens who eloped to marry the men they loved

Ruhi Bhasin

Shunned by their families for eloping and marrying the men they loved, two girls, both 17, and from different districts in Haryana, ended up at the Nari Niketan in Karnal. Last Tuesday, they allegedly committed suicide after a failed attempt to run away from the home for women — both were found hanging in a bathroom. But in death too, their parents refused to accept them. The last rites have been carried out by a local NGO.

While one girl belonged to Mahendragarh, the other was from Kaithal district. They reached the Nari Niketan a day apart — one last Saturday and the other on Sunday. Officials claimed that within a few hours of meeting each other on Sunday, the girls decided to run away to Kaithal and fled the same night after scaling the walls of the complex. But they were caught and returned.

While the parents of the girl from Mahendragarh came to identify her, they refused to carry out her last rites.

Karnal Deputy Commissioner Renu Phulia said: "We offered to help them take her body home but they refused. A local NGO carried out the last rites on Wednesday. After waiting three days for the family of the other girl, the NGO carried out the last rites on Friday. Her family refused to come."

The district administration has ordered a probe to ascertain the cause behind their deaths. The inquiry will be conducted by a sub-divisional magistrate.

Officials at the Nari Niketan claimed that "both girls seemed perfectly normal before their death". This was corroborated by counsellors who spoke to them after they were brought from Kaithal.

"They had tea in the evening and were present for the roll call. But when the attendant was handing over charge to the next in the shift, the two girls were missing. A search was carried out and the girls were found hanging in the bathroom, dangling from overhead water pipes,'' Phulia said.

Kidnapping, abducting or inducing a woman to compel her marriage.

Karnal SP Shashank Anand said: "Both girls were sent to the Nari Niketan as per orders of local magistrates. They did not wish to go back to their parents as they felt that their safety was threatened there. They were from different districts, brought together by similar circumstances of eloping, marrying while being underage."

According to Phulia, the Nari Niketan is home to girls from across Haryana and most cases relate to underage marriage. "Most of them are brought here after complaints made by parents,'' she said.

The father of the girl from Kaithal said she went missing on June 18. He alleged she was raped. "We filed a case with the local police but nothing was done. My girl was raped and was forced to make a false statement about a love marriage. Until the rapists are caught, we will not carry out her last rites,'' he said.

Anand said the police have asked doctors to examine the rape aspect as well.

(Courtesy - The India Express)

VOICE OF BUDDHA

Publisher : Dr. UDIT RAJ (RAM RAJ), Chairman - Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42

● Year : 16 ● Issue 16 ● Fortnightly ● Bi-lingual ● 1 to 15 July, 2013

NATIONAL CONVENTION ON EDUCATION POLICY

ON 8TH SEPTEMBER, 2013 AT CONSTITUTION CLUB, NEW DELHI.

For the last one decade, education has become the most secure and money-spinning profession. It is because of education that a country progresses and for the same reason, it goes down. Even though country is making economic progress, but to maintin its tempo, eduation for all is most important. Government has taken several steps to eliminate poverty from our country but it will continue to be a distant goal unless the people of the country are educated.India will become a world leader the day equal education is made available to all the citizens. The present system of education is employment-oriented and not for dissemination of true knowledge. Good education is limited only to the rich.

Four-year undergraduate programme has been introuduced by Delhi University on the plea that it is employment-oriented and it is so in America also. Is it imperative that whatever is done in America should be done in India also? Whenever questions are raised on any issue, the stock reply is that it is being done in America like that. In America and Europe, there is very little interest for higher education in most of the people but in our country, the reality is different. Despite the high salary of a highly educated person, his social status and prestige inb America or Europe, does not have much of an impact on a less educated person. In our country, higher education is directly connected with higher income, social status, knowledge and opportunities and many other factors. The hidden agenda of Delhi University's 10+2+4 new education policy is to speed up the process of privatization and to make higher education so costly that it becomes beyond the reach of SC/ST, Backwards, rural and other poor people. 10+2+3 eduation policy was approved by the Parliament in the year 1986 which has been overturned by the Delhi University Vice-Chancellor. As the Delhi University Vice-Chancellor has introduced the 10+2+4 undergraduate programme for the benefit of the rich and for speeding up privatization, there is no likelihood of disciplinary action against him, rather it has been strongly supported by the HRD Ministry and the Prime Minister Office.

Unfortunately, the political class is not serious about the education policy of the country. When elections are held on the issues like education, the condition and direction of the country will change. The Joint Action Front For Democratic Education (SC/ST/OBC/Left) came into existence with a view to oppose the introduction of the four-year undergraduate programme in Delhi University but gradually it was felt that the issue is much bigger and it is not easy to fight it out and therefore, it was decided to widen the scope of the movement. 4500 posts of teachers are lying vacant in Delhi University and our Front was working for this issue also but now it has been decided that this movement should be organized on a national scale. It has, therefore, been decided that a National Convention will be held on Education Policy on the 8th September, 2013 (Sunday) at the Speaker Hall, Constitution Cluib, New Delhi for nine hours in which teachers, intellectuals and social activists will be invited from all over the country. Our main demand will be equal education for all which means the education which is being availed by the children of industrialists, ministers and bureaucrats should be given to all the children between the age of 4 and 14 . This demand is absolutely justified and the people who are never tired of justifying the four-year undergraduate programme of Delhi University should also remember that in America there is no difference between the education imparted in Government and Private schools, rather Government schools are imparting better education. After a consensus is arrived on the basis of day-long discussions, a national movement will be launched on that basis. By the time of the 2014 Lok Sabha elections, it should become a very strong election issue for all the political parties. In the beginning, this movement started with the help of only a few organizations but in the days to come, hundred and thousands of organizations will come undker our banner. The organizations which initially joined the Front are Indira Athawale, Vinod Kumar (All India Confederation of SC/ST Organizations), Dr. Hani Babu (A.S.J), Vijaya Venkatraman, Dr. Shaswati Majumdar and Abha Dev (CPM), Prem Singh (S.T.A), Dr. S. K. Sagar (F.O.C.U.S), Dr. Kedar Kumar Mandal (A.F.S.J.), Dr. Nandini Data (C.T.F.), Dr. Hans Raj Suman (F.A.S.J), Pal Divakar (N.C.D.H.R), P. Abdul Nazar (C.F.I), Harshvardhan Dawane, Dinesh Ahirwar (N.S.O.S.Y.F),Vinay Bhushan (A.I. B.S.F), Anoop Patel (S.U.I), Lenin Vinobar (S.S.J), Dr. Kaushal Kishor Pawar, Prof. Hem Lata Maheshwar, Dr. Sukumar, G.N. Saibaba, etc.

Coordinator
Dr. Udit Raj,
National President,
All India Confederation of SC/ST Organizations.

Terrorist Attack on Bodhgaya Highly Condemned - Udit Raj

Dr. Udit Raj, National Chairman of the All India Confederation of SC/ST Organizations, said that bomb attacks were made on the morning of 7.7.2013 at Bodh Vihar and surrounding areas of the Foreign Missions in Bodh Gaya, due to which extensive damage has been caused. After the ghastly attack, not only the Indian tourists and the local Buddhists are scared but also the foreign missions located there are in the grip of fear due to this attack.In November 2012 and on 21st June and 3rd July, 2013, the Security Agencies like Intelligence Bureau and Delhi Police etc. had warned Bihar Government of an impending terrorist attack but the Bihar Government failed to take suitable timely action and the results are there for anybody to see. The Bihar Government, which takes credit for good governance is to be blamed solely for this serious lapse. It was not difficult to prevent the attack when the Bihar Government had got advance information about the impending attack.

Dr. Udit Raj is a Buddhist leader of international standing and under his leadership, lakhs of people were converted to Buddhism, which fact is known not only in India but all over the world. He regretted that for political gains, some of the leaders doubt the veracity of the advance information given by the Government security agencies which is not good for the country. Maybe, the inputs given by the government security agencies are not always correct, but when some information is given in advance, the concerned government must seriously work on it. Not to trust these inputs or take them lightly just tantamounts to paying a heavy price for this attitude which precisely has happened in the case of Bodh Gaya. On 8.7.2013, an emergency meeting of the Buddhist community was held at T-22, Atul Grove Road, New Delhi-110001, in which this dastardly attack was condemned and it was demanded that the culprits may be nabbed immediately and suitable punishment awarded to them. It is not only an attack on Buddhism but an attempt to discourage the tourists from going to Bodh Gaya which will also affect the economic progress of the State of Bihar.

Dr. Udit Raj is also National Chairman of Lord Buddha Club and Buddha Education Foundation. He said that the law and order situation in the Bihar is highly deplorable. Day in and day out tourists visiting Bihar become victims of crime and attacks on foreign missions including theft and burglaries are quite frequent. Lighting arrangement at the tourist places is not adequate, due to which not only terrorist attacks but accidents etc. can also take place. Had there been adequate lighting arrangements in the area, perhaps the 7th July attack could have been averted. Maintenance is absolutely inadequate.

Publisher, Printer and Editor - Dr. UDIT RAJ (FORMERLY KNOWN AS RAM RAJ), on behalf of Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42, Telefax:23354843, Printed at Sanjay Printing Works, WZ-4A, Basai Road, New Delhi.
Website : www.uditraj.com E-mail: dr.uditraj@gmail.com Computer typesetting by N. K. Karn